एलआईसी में 1,100 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश

पहले दिन नियमित एंडोमेंट उत्पादों से भारी निवेश दर्ज.

सितंबर शुरुआत में बिक्री रुकी, कर छूट के बाद बढ़ी.

नई दिल्ली. 28 सितंबर, जीवन बीमा पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) समाप्त होने के पहले ही दिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1,100 करोड़ रुपए से अधिक का भारी निवेश मिला. यह आँकड़ा उन लोगों के हवाले से सामने आया है जो इस मामले से परिचित हैं.

यह रिकॉर्ड इनफ्लो अगस्त महीने में खुदरा पॉलिसीधारकों से मिले 5,000 करोड़ रुपए के मासिक प्रीमियम आय की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है.इस निवेश का अधिकांश हिस्सा नियमित एंडोमेंट उत्पादों से आया है, न कि किसी नई बीमा योजना से.

रुकी हुई माँग का फूटना- बीमा क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी में बदलाव की उम्मीद के चलते सितंबर की शुरुआत में एलआईसी की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कम रही थी. एजेंट और ग्राहक 22 सितंबर से लागू होने वाले कर परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे थे. नई व्यवस्था प्रभावी होते ही यह रुकी हुई माँग अचानक बाजार में आ गई, जिसके कारण पहले ही दिन रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया.हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पूरे उद्योग पर इस बदलाव का दीर्घकालिक रुझान कुछ महीनों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

सभी पॉलिसियाँ हुईं कर मुक्त- जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर, 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा की सभी पॉलिसियों को शून्य कर श्रेणी में डाल दिया है. इस छूट के दायरे में टर्म प्लान, यूनिट-लिंक्ड और पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद, साथ ही फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाओं जैसे स्वास्थ्य कवर भी शामिल हैं.

पॉलिसी घटी, पर प्रीमियम बढ़ा

अप्रैल से अगस्त 2025 के दौरान, नए कारोबार प्रीमियम में पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से टिकट साइज़ (प्रीमियम की औसत राशि) बढ़ने के कारण हुई, जबकि पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि धीमी रही.इस अवधि में निजी बीमा कंपनियों ने 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि एलआईसी 3 प्रतिशत की वृद्धि पर रही. कुल मिलाकर, अप्रैल-अगस्त 2025 में नया कारोबार प्रीमियम बढ़कर 1,63,461 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले यह 1,54,193 करोड़ रुपए था.

चावल-गेहूं नरम, चीनी मजबूत, खाद्य तेलों-दालों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 28 सितंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव में नरमी रही. गेहूं में भी मंदी देखी गयी. चीनी के भाव बढ़ गये जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव रहा. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत छह रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,836.87 रुपये प्रति क्विंटल पर रही. गेहूं 23 रुपये सस्ता होकर 2,839.85 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका. आटे की कीमत भी छह रुपये घट गयी और सप्ताहांत पर यह 3,317.28 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. बीते सप्ताह सरसों तेल की औसत कीमत 129 रुपये प्रति क्विंटल गिरी. मूंगफली तेल में भी 41 रुपये और सोया तेल में 50 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया.

मुंबई के ताज सांताक्रूज में उद्योग बैठक आयोजित

पुणे, 28 सितंबर. बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह संघ के साथ मिलकर आज मुंबई के ताज सांताक्रूज़ में एक उद्योग बैठक का आयोजन किया, जो इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 से पहले की श्रृंखला कार्यक्रमों का हिस्सा थी.

25 सितंबर 2025 को आयोजित इस बैठक में लगभग 60 प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और समुद्री उद्योग के नेता शामिल हुए, जिनमें प्रमुख समुद्री कंपनियों के सीईओ भी मौजूद थे. इस सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय मंत्री (बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग), डॉ. एम. अंगमुथु, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण, कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी, सीएमडी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, श्री उमेश वाघ, अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण तथा श्री आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव (बंदरगाह) उपस्थित रहे.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणमान्य अतिथियों के औपचारिक स्वागत से हुई. इसके बाद श्री अंगमुथु, अध्यक्ष, रूड्डक्क ने आईएमडब्ल्यू की रूपरेखा और स्वागत भाषण प्रस्तुत किया.

अपने वक्तव्य में अध्यक्ष ने मंत्रालय की अल्प और मध्यम अवधि की योजना साझा की, जिसमें भारत के समुद्री परिवर्तन पर जोर दिया गया है—क्षमता विस्तार, अवसंरचना आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के जरिए. उन्होंने आंतरिक जलमार्ग और तटीय नौवहन को मजबूत करने, शिपबिल्डिंग और शिप रिपेयर क्षमता को बढ़ावा देने, तथा सतत बंदरगाह प्रथाओं को प्रोत्साहित करने पर मंत्रालय का फोकस रेखांकित किया—जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और टर्मिनलों पर विद्युतीकरण की पायलट परियोजनाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने व्यापार सुगमता सुधारने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को गहरा करने के उपाय बताए.

रणनीतिक प्राथमिकताएं बताईं

सर्बानंद सोनोवाल ने सभा को संबोधित किया और आईएमडब्ल्यू 2025 से पहले एक हरित, लचीला और विकासोन्मुख समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार की दृष्टि को दोहराया. उन्होंने जलमार्गों की ओर मोडल शिफ्ट को बढ़ावा देने, क्रूज़ और तटीय पर्यटन का विस्तार करने, शिपबिल्डिंग और रीसाइक्लिंग क्षमताओं का निर्माण करने, तथा जहाजों व बंदरगाह संचालन के डिकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने की रणनीतिक प्राथमिकताएँ बताईं.

एफपीआई ने सितंबर में बेची 17,551 करोड़ रुपये की इक्विटी

मुंबई 28 सितंबर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में अब तक शेयर बाजार में 17,551 करोड़ रुपये की इक्विटी की शुद्ध बिकवाली की है. यह निवेशकों द्वारा निकाली गयी कुल राशि और उनके द्वारा लगायी गयी कुल राशि का अंतर होता है.

सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में एफपीआई ने शेयर बाजार से 17,551 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की. उन्होंने यूचुअल फंड से भी 1,192 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की.

वहीं एफपीआई ने डेट में 12,770 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. हाइब्रिड में उन्होंने 1×4 करोड़ रुपये का निवेश किया. इस प्रकार सितंबर में उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार से 5,8×6 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की.

यह लगातार चौथा महीना है जब एफपीआई बिकवाल रहे हैं. इससे पहले अगस्त में उन्होंने 20,635 करोड़ रुपये, जुलाई में 5,261 करोड़ रुपये और जून में 7,769 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी. इस साल मार्च और मई को छोड़कर अन्य सात महीने एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले हैं. पूरे कैलेंडर वर्ष में उन्होंने कुल 77,875 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है.

एसईसीएल ने शुरू किया 'स्व' छोत्सव 2025

ई-वेस्ट प्रबंधन और शून्य अपशिष्ट उत्सव पर विशेष जोर

नागपुर, 28 सितंबर. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने इस वर्ष स्व' छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 'स्व' छोत्सव- स्वच्छ और हरित उत्सव, शून्य-अपशिष्ट' थीम के साथ की है. इस बार अभियान का मुख्य फोकस कचरा प्रबंधन और ई-वेस्ट के संग्रह एवं रीसाइक्लिंग पर रखा गया है. यह अभियान 2 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 5.0 की तैयारी चरण के रूप में चलेगा.

अभियान का शुभारंभ एसईसीएल मु यालय और सभी परिचालन क्षेत्रों में स्व' छता शपथ दिलाकर किया गया. बिलासपुर मुख्यालय में स्व' छता संदेश देने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आकर्षक रंगोली भी बनाई गई.

इस वर्ष एसईसीएल ने विशेष रूप से ई-वेस्ट प्रबंधन को केंद्र में रखा है और इसके लिए संग्रह एवं रीसाइक्लिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

इसके साथ ही कपड़े के बैनर प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे, स्व' छता प्रतियोगिताएँ होंगी, 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत वृक्षारोपण होगा तथा सफाई मित्रों का स मान भी किया जाएगा.

स्पेशल कैंपेन 5.0 का क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य स्व' छता प्रथाओं को संस्थागत रूप देना, सतत विकास को मजबूत करना और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करना है.

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मंजूर

नई दिल्ली. 28 सितंबर. भारत ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के लिए तैयार है. एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सबसे कम लागत वाला हाइड्रोजन आपूर्तिकर्ता बनने की जबरदस्त क्षमता है.

हालांकि, यह क्षमता बनाए रखने के लिए भारत को अपने शुरुआती गति को बरकरार रखना होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के सामने ऑफटेक (खरीद) समझौतों को सुरक्षित करना होगा.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि

भारत अपने मजबूत एसेट्स बेस के कारण ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास में दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है. रिपोर्ट में हाइड्रोजन क्षमताएं विकसित करने में भारत की प्रभावशाली प्रगति और वैश्विक हाइड्रोजन उद्योग में देश की अग्रणी भूमिका पर ज़ोर दिया गया है.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

मिशन 2030- 50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन

भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले ही एक मजबूत नींव रख दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी.

हरित ऊर्जा और स्मार्ट मोबिलिटी में भारत का साथी बनना चाहता है ताइवान

नई दिल्ली, 28 सितंबर. तेज़ी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अब वैश्विक तकनीकी साझेदारों को आकर्षित कर रही है. इस कड़ी में ताइवान ने संकेत दिया है कि वह केवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं रहकर हरित ऊर्जा, स्मार्ट मोबिलिटी और स्वास्थ्य तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी भारत के साथ साझेदारी को मज़बूत करना चाहता है. भारत और ताइवान के बीच व्यापारिक रिश्ते अब एक नए मोड़ पर हैं. ताइवान न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में भारत का सहयोगी बना रहना चाहता है.

राष्ट्रीय पर्यटन विकास पर सेमिनार आयोजित

विकास की कुंजी के रूप में रेखांकित किया

पर्यटन वृद्धि को तेज करने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श

नई दिल्ली, 28 सितंबर. फाउंडेशन फॉर एविएशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के समर्थन से नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पर्यटन विकास पर सेमिनार का आयोजन किया.

इस सेमिनार में वरिष्ठ नीति निर्धारक, उद्योग के विशेषज्ञों ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच भारत की पर्यटन वृद्धि को तेज करने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया.

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत, ने 2 अपने संदेश में ओर से आयोजित वर्तमान घरेलू एवं वैश्विक चुनौतियों और भारत के तेजतर्रार पर्यटन विकास का रोडमैप पर सेमिनार के लिए अपना समर्थन और बधाई दी.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में पर्यटन के परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला, जो डिजिटल तकनीकों और महामारी के बाद पुनरुद्धार से प्रेरित है, और आने वाले दशक को स्वर्णिम युग बनाने के लिए फोकस और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया.

शेखावत ने कहा कि पर्यटन की सच्ची सफलता केवल आर्थिक वृद्धि में नहीं बल्कि समुदायों को सशक्त बनाने और भारत की सांस्कृतिक गहराई एवं विरासत को प्रतिबिंबित करने में निहित है. मु य वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ, (सेवानिवृत्त), जो त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के पूर्व रा'यपाल हैं, ने एक मजबूत पर्यटन उद्योग की वकालत की, जिसमें सहयोग के मॉडल के माध्यम से नवाचारी पर्यटन उत्पाद विकसित किए जाएं और स्थिर अ यास विश्व मानकों के अनुसार लागू हों. अन्य प्रमुख वक्ताओं में विनोद (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, पर्यटन मंत्रालय; अतुल भल्ला, उपाध्यक्ष संचालन ने आभार व्यक्त किया.

समाचार विशेष

गठबंधन से आगे सोच रही है कांग्रेस

घटक दलों पर दबाव की रणनीति

नई दिल्ली. अब तक कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां या कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता, जिनका पार्टी से मोहभंग हो रहा था वे विपक्षी गठबंधन यानी 'इंडिया' ब्लॉक के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे. पी चिदंबरम जैसे कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए थे. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुद ही विपक्षी गठबंधन से आगे सोच रही है.

बिहार में कांग्रेस पार्टी गठबंधन से आगे निकलने की सोच में काम कर रही है तो तमिलनाडु में भी पार्टी के नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. जिस तरह से बिहार में कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर दबाव बना रहे हैं वैसा ही दबाव

तमिलनाडु में डीएमके के ऊपर बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी यह दांव आजमाने की तैयारी चल रही है. कांग्रेस के जानकार नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की सक्रियता से और वोट चोरी के मुद्दे पर उनकी लड़ाई ने कांग्रेस के नई ताकत दी है. अब देश भर में कांग्रेस को ही असली और मजबूत विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है. इसलिए कांग्रेस अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहती है.

बिहार में कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को कई तरह से घेरा है.

डीएमके पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव

इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस नेताओं ने पुराना फॉर्मूला छोड़ कर डीएमके पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने लगे हैं. कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार के बयान के बाद पंडोरा बॉक्स खुला है. इसमें नई पार्टी बना कर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे तमिल सुपरस्टार विजय ने भी थोड़ी भूमिका निभाई है. वे कांग्रेस के साथ तालमेल का संकेत दे रहे हैं. डीएमके के बिना डीएमके अलायंस की बात हो रही है. उनकी ओर से कहा जा रहा है कि डीएमके जिस वोट का प्रतिनिधित्व करती है उसे डीएमके के बगैर भी साथ लिया जा सकता है.

मेवाराम जैन के कांग्रेस में वापसी के संकेत!

बाड़मेर. राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. कांग्रेस से निष्कासित बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी हो सकती है.

जैन की कांग्रेस में वापसी की सुगबुगाहट मात्र से बाड़मेर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. मेवाराम के पार्टी में वापसी के संकेत मिलते ही बाड़मेर कांग्रेस के दिग्गज नेता इसके विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने दिल्ली में डेरा जमा लिया है. इससे यहां कांग्रेस दो

खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है. मेवाराम बाड़मेर से लगातार तीन बार विधायक रह चुके हैं. भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले में किसी समय कांग्रेस में मेवाराम जैन बड़ा नाम रहा है. सूत्रों के मुताबिक जैन की वापसी के संकेत मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस के नेता इसके विरोध में लामबंद हो गए हैं. सीडब्ल्यूसी सदस्य बाड़मेर के बायतु विधायक हरीश चौधरी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित सभी नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है. माना जा रहा है कि भाजपा 2026 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस त्योहार के जरिये लोगों से जुड़ने की रणनीति बनाई है.

बता दें कि चुनावी अभियान के तहत भाजपा ने इस बार सौ से ज्यादा नेताओं को देश के दूसरे राज्यों में भेजा है ताकि वे वहां बसे बंगाली प्रवासियों से संपर्क कर सकें. रणनीति के तहत पश्चिम

दुर्गा पूजा बनी चुनावी अभियान का हिस्सा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है. इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है. आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है.

ऐसे में जहां एक ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपने विपक्षी दल भाजपा पर बंगाली विरोधी होने के आरोपों के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा ने भी इसके जवाब के लिए चुनावी रण में दुर्गा पूजा को अपने राजनीतिक अभियान का अहम हिस्सा बना

बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य गुजरात में, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार वाराणसी में और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी त्रिपुरा में मौजूद रहेंगे. भाजपा ने साल्ट लेक के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर (ईजडसीसी) में अपनी दुर्गा पूजा को फिर से शुरू किया है, जो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शुरू हुई थी, लेकिन 2021 के चुनाव में हार के बाद इसे बंद कर दिया गया था. इस साल यह पूजा भाजपा समर्थित संस्था %पश्चिम बंग संस्कृत मंच% द्वारा आयोजित हो रही है. इसके साथ ही भाजपा ने पूजा पंडालों में किताबों के स्टॉल भी बढ़ा दिए हैं.

तरह-तरह के आयोजनों पर भी जोर

पार्टी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया है, जिसमें इनाम वाले कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं. माना जा रहा है कि भाजपा इस अभियान के जरिए टीएमसी के बाहरी होने का आरोप खारिज कर अपनी बंगाली पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. वहीं दूसरी ओर टीएमसी इस कोशिश को महज दिखावटी कदम बता रही है और कह रही है कि इससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. गौरतलब है कि दुर्गा पूजा में टीएमसी का प्रभाव अभी भी मजबूत है, लेकिन भाजपा की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को काफी बदल दिया है. ऐसे में चुनाव से पहले यह सांस्कृतिक युद्ध अब और गहरा होने वाला है.

विशेष | 57 प्रतिशत महिला नेता खानदानी, इस पार्टी का है दबदबा

परिवारवाद की जंजीरों में जकड़ी राजनीति!

पटना. भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है. देश के कई राज्यों में नेता का बेटा नेता, बेटी विधायक और भाई सांसद बनता दिखाई देता है. बिहार में भी यह तस्वीर कुछ अलग नहीं है. राज्य में चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं की बड़ी संख्या किसी न किसी राजनीतिक घराने से आती है.

हालिया आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 27 प्रतिशत विधायक, सांसद और विधान पार्षद खानदानी राजनीति की देन हैं. महिला नेताओं के मामले में यह आंकड़ा और भी अधिक है. बिहार की करीब 57प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं. इसका मतलब साफ है कि महिलाओं की राजनीति में एंट्री अभी भी मुख्य रूप से पारिवारिक विरासत पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत संघर्ष या क्षमता पर. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार देश के उन राज्यों में चौथे नंबर पर आता है, जहां वंशवाद की जड़ें सबसे गहरी हैं. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद बिहार का स्थान आता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य की राजनीति सिर्फ जनाधार पर नहीं, बल्कि परिवार की विरासत पर भी निर्भर करती है.

पार्टीवार आंकड़े पर एक नजर- राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में सबसे अधिक वंशवाद देखने को मिलता है. बिहार में कांग्रेस के 32 प्रतिशत जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं. वहीं, भाजपा में यह आंकड़ा 17 प्रतिशत है. क्षेत्रीय दलों में स्थिति और भी स्पष्ट है. लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और आजसू पार्टी के 50 प्रतिशत जनप्रतिनिधि खानदानी हैं. राजद और जदयू में यह अनुपात लगभग 31 प्रतिशत तक पहुंचता है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जहां एक-दो परिवारों का दशकों तक दबदबा न रहा हो. चाहे गया हो, नवादा हो, जमुई हो या पटना. हर जगह किसी न किसी परिवार की पकड़ कायम है.

लालू यादव से लेकर मांझी तक परिवारों का दबदबा

बिहार की राजनीति में बड़े परिवारों का नाम लेने पर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का परिवार सामने आता है. लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य पूरा परिवार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. रामविलास पासवान की विरासत अब उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं. वहीं, जीतन राम मांझी का परिवार भी राजनीति में ऐक्टिव हैं.